लिए सृजित अन्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सभी पात्र विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान प्रदान करता है। विशेष सहायता की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान प्रदान किए जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने 8वीं योजना के दौरान राजस्थान में विश्वविद्यालयों के लिए 385.00 लाख रु० की धनराशि का विकास अनुदान आवंटित किया है।

Central Assistance for Literacy Programme

1489. SHRI RAMDAS AGARWAL Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) Whether Government propose to change the funding pattern for total literacy campaign (T.L.C.) between Centre and Rajasthan State from the present 2 : 1 to hundred per cent central assistance because of its lowest literacy rate in the country ;

(b) Whether Government are aware that in some districts like BARMER and JALORE, the female literacy percantage is less than 5 per cent as per 1991 census; and

(c) If so, the amount of central assistance likely to be provided to the State during 1992-93 and during Eighth Five Year Plan period for streamlining educational activities particularly girls' education in that State ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) No Sir.

(b) The estimated female literacy in Barmer and jalore, according to 1991 census, is 7% and 6·8% respectively.

(c) Since the proposal for 1992-93 in respect of Rajasthan would be made only during the next financial year, it is not possible to indicate at this stage the likely assistance for 1992-93.

देश में साक्षरता

1490. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1991 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 48 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने देश में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने इसके लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ क्या कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार देश में 7 वर्ष और इससे अधिक आयु वाली जनसंख्या की साक्षरता दर 47.89 थी।

(ख) से (घ) स्कूल छोड़ जाने वालों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सहित प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसका लक्ष्य वर्ष 1995 तक 15–35 आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, देश में निरक्षरता उन्मूलन के व्यापक कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मुख्य कार्य नीति पूर्ण साक्षरता अभियानों को आयोजित करना है जो क्षेत्र विशिष्ट समय-बद्ध और स्वैच्छिक सेवा पर आधारित होंगे। यद्यपि पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया, फिर भी आशा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण साक्षरता अभियानों द्वारा लगभग 75–80 प्रतिशत जिलों को शामिल कर लिया जाएगा और देश में साक्षरता दर बढ़कर 70 प्रतिशत के आसपास हो जाएगी।